RNI No.: UPHIN/25/A1697
GARVI GUJARAT
गरवी गुजरात
गरवी गुजरात
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक
वर्ष : 02
अंक : 009
दि. 09.05.2026, शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

भारत ने पहली बार 'अंतरिक्ष प्रणाली और संचालन' पर आईएसओ की अंतरराष्ट्रीय उपसमिति की बैठकों की मेजबानी की

भारतीय मानक ब्यूरो अंतरिक्ष सुरक्षा, संचालन और सततता के भविष्य को आकार देने के लिए अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को एक मंच पर लाया

13 देशों के 131 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया

इसमें मिशन सुरक्षा, अंतर-संचालनीयता और कचरे को कम करने सहित अंतरिक्ष प्रणालियों के संपूर्ण जीवनचक्र के मानकों पर ध्यान केंद्रित किया गया

(जीएनएस)। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), जो भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है, ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) की आईएसओ टीसी 20/ एससी 14 'अंतरिक्ष प्रणाली और संचालन' उपसमिति की 35 वीं प्लेनरी और कार्य समूह की बैठकों का आयोजन किया। स

नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव सुश्री निधि खरे ने मानकों को आगे बढ़ाने में वैश्विक सहयोग के महत्व और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष मानक इकोसिस्टम को आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "भारत के लिए इस बैठक की मेजबानी करना अत्यंत गौरव का विषय है, क्योंकि हम वैश्विक अंतरिक्ष परिवर्तन के अग्रणी के रूप में खड़े हैं। महत्वपूर्ण सुधारों और आईएन-एसपीएसीई की स्थापना के माध्यम से भारत सरकार ने एक उभरते हुए अंतरिक्ष केंद्र की नींव रखी है, जहां स्टार्टअप और स्थापित उद्योग समान रूप से फल-फूल सकते हैं। इस तरह के वैश्विक सहयोग और विशेषज्ञता द्वारा विकसित मानक मानवता के लिए अंतरिक्ष को सुरक्षित, सतत और समावेशी बनाने में मदद करेंगे।"

इस अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के महानिदेशक संजय गर्ग ने भारत के बढ़ते अंतरिक्ष क्षेत्र में गुणवत्ता, सुरक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने में मानकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बीआईएस अंतरिक्ष उद्योग की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय मानकों को अंतरराष्ट्रीय ढांचों के अनुरूप बनाने की दिशा में काम कर रहा है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के तेजी से होते बदलाव को रेखांकित करते हुए उन्होंने उल्लेख किया कि बीआईएस मानक निजी क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में इस बैठक की मेजबानी करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारतीय विशेषज्ञों को मानकीकरण प्रक्रिया में सीधे भाग लेने का अवसर देती है, जिससे राष्ट्रीय इकोसिस्टम और वैश्विक मानकीकरण प्रयासों दोनों को मजबूती मिलती है।

डॉ. पवन गोयनका (अध्यक्ष, आईएन-एसपीएसीई) ने नीतिगत सुधारों और निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्रेरित भारत के अंतरिक्ष इकोसिस्टम के परिवर्तनकारी विकास पर बल दिया। उन्होंने नवाचार को सक्षम करने, उद्योग के विश्वास को बढ़ाने और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत के एकीकरण को सुविधाजनक बनाने में मजबूत मानकों के महत्व को रेखांकित किया।

इस कार्यक्रम में 13 देशों के 131 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें विभिन्न राष्ट्रीय मानक निकायों के प्रतिनिधि, भारत की आईएसआरओ सहित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के विशेषज्ञ, अंतरिक्ष उद्योग और शिक्षाविद् शामिल थे।

उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव सुश्री निधि खरे; बीआईएस के महानिदेशक श्री संजय गर्ग; डॉ. पवन गोयनका (आईएन-एसपीएसीई के अध्यक्ष); बीआईएस की उप महानिदेशक (मानकीकरण) सुश्री रीना गर्ग; श्री फ्रेडरिक स्लेन (आईएसओ टीसी 20 / एससी 14 के अध्यक्ष) और श्री राजीव ज्योति (एयर एंड स्पेस व्हीकल्स संबंधी बीआईएस समिति टीईडी 14 के अध्यक्ष) उपस्थित थे।

आईएसओ/टीसी 20/एससी 14 डिजाइन और उत्पादन से लेकर प्रक्षेपण, संचालन और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं तक अंतरिक्ष प्रणालियों के संपूर्ण जीवनचक्र के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक विकसित करता है, जिससे यह वैश्विक अंतरिक्ष गतिविधियों में सुरक्षा, अंतर-संचालनीयता और सततता सुनिश्चित होती है। इस प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करना वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की बढ़ती स्थिति को दर्शाता है, जिसे आईएसआरओ की उपलब्धियों और आईएन-एसपीएसीई के माध्यम से सक्षम हुई निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी से बल मिला है। यह बैठक अंतरिक्ष सततता, कचरे को कम करने और मिशन संचालन जैसे उभरते क्षेत्रों में वैश्विक मानकों को आकार देने में भारत की सक्रिय भूमिका को भी दर्शाती है।

सीएम योगी का अफसरों को सख्त फरमान; सांसद-विधायक मिलने पहुंचें तो खड़े होकर करें सम्मान

यूपी के बजट सत्र में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय ने अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाया था.

(जीएनएस)। लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बड़ा आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिया है कि कोई भी अधिकारी अब जनप्रतिनिधियों के प्रति पूरा सम्मान रखेगा. वढ के आईएएस-आईपीएस और अन्य अधिकारी विधायकों और सांसदों का खड़े होकर स्वागत सम्मान, जल ग्रहण करने का आग्रह करेंगे. विधायकों और सांसदों का फोन नंबर उवङ्क नम्बर सेव करेंगे.

फोन न उठाने पर दुबारा फोन करेंगे. ऐसा न करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर करवाई भी की जाएगी.

यूपी के मुख्यसाचिव रढ गोयल ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव DGP और DM को निर्देश दिया है. यूपी के बजट सत्र में फरवरी में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय ने अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर सदन में सवाल उठाया था, जिसके बाद यूपी के मुख्य सचिव ने सांसद और विधायकों के प्रोटोकॉल को लेकर नया शासनादेश जारी किया.

बजट सत्र में माता प्रसाद पांडेय ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा था एक बार तो जिले के एसपी फोन उठा लेते हैं, लेकिन थानेदार को फोन करने पर वह नहीं उठाता है.

पश्चिम बंगाल की जीत को गुजरात मंत्री ने बताया 'दूसरी आजादी', पीएम मोदी के सोमनाथ दौरे की तैयारियां तेज

गिर सोमनाथ (जीएनएस)। मंत्री ने बताया कि 'सोमनाथ अमृत पर्व' समारोह में पुनर्निर्मित तीर्थस्थल की 75 साल की यात्रा को दशार्ने वाली प्रदर्शनियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। ये दुनिया भर के भक्तों के लिए आस्था और राष्ट्रीय गौरव का एक जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इन समारोहों का उद्देश्य आगंतुकों को एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करना है।

गुजरात के कृषि एवं प्रवक्ता मंत्री जीतू वाघाणी ने भाजपा के पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रदर्शन को "दूसरी आजादी" बताया है। उन्होंने कहा कि यह नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास पर जनता की स्वीकृति को दशार्ते हैं। मंत्री का यह बयान प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे से पहले सोमनाथ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में दिया गया।

मंत्री वाघाणी ने कहा, "भारत की स्वतंत्रता के बाद बंगाल में जो जीत हासिल हुई है, वह दूसरी आजादी के समान है।" उन्होंने यह कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 'सोमनाथ अमृत पर्व' में उपस्थिति हम सभी के लिए गर्व और खुशी का विषय होगी।

जीतू वाघाणी ने सोमनाथ मंदिर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐतिहासिक आक्रमणों के बावजूद मंदिर अपनी आस्था और पहचान पर अटल रहा है और सनातन धर्म का प्रतीक बना हुआ है। उन्होंने बताया कि मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ गुजरात और राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण था और प्रधानमंत्री के आगमन का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

मंत्री वाघाणी ने सोमनाथ मंदिर से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को याद किया, जिसमें सरदार वल्लभभाई पटेल की सोमनाथ यात्रा का उल्लेख था। उन्होंने कहा कि पटेल मंदिर की जर्जर हालत से द्रवित थे और उन्होंने समुद्र का जल लेकर इसके पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। उन्होंने यह भी बताया कि पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का अभिषेक समारोह 11 मई, 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था।

इसके 75 वर्ष पूरे होने को 'सोमनाथ अमृत पर्व' के रूप में मनाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के लिए की जा रही व्यवस्थाओं की रूपरेखा बताते हुए मंत्री वाघाणी ने कहा, "पीएम जामनगर से सोमनाथ आएंगे और त्रिवेणी हेलीपैड से वीर हमीरजी गोहिल की प्रतिमा तक एक रोड शो करेंगे, जिसकी दूरी लगभग एक किलोमीटर होगी।" इस मार्ग पर विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली नृत्य प्रस्तुतियों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।

इसके साथ ही 12 ज्योतिलिंगों की झलक भी दिखाई जाएगी। मंदिर परिसर में, ऋषिकुमार और पारंपरिक वेशभूषा में अहीर समुदाय के सदस्य प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा में बंगाली परिवारों की भागीदारी भी शामिल होगी।

'विकास भी, विरासत भी', सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने लिखा लेख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर लिखे अपने विशेष लेख में इसे भारत की अपराजित आत्मा, सांस्कृतिक चेतना और सभ्यता के अटूट संकल्प का प्रतीक बताया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को लेकर एक भावनात्मक और ऐतिहासिक लेख लिखा है, जो कई अखबारों में प्रकाशित हुआ है. अपने लेख में पीएम मोदी ने कहा कि साल 2026 की शुरूआत में उन्हें सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होने का सौभाग्य मिला था. यह आयोजन सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के एक हजार वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया था।

कांग्रेस ने छोड़ा डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन का साथ, अखिलेश ने थामा हाथ! बोले- मुसीबत में साथ छोड़ने वाले नहीं

(जीएनएस)। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर जारी सियासी उठापटक अब राष्ट्रीय विपक्षी राजनीति तक पहुंच गई है। कांग्रेस द्वारा डीएमके से दूरी बनाकर विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) को समर्थन देने के फैसले के बाद INDIA गठबंधन के भीतर असहजता खुलकर सामने आने लगी है।

इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर अप्रत्यक्ष हमला बोलते हुए बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है।

अखिलेश यादव ने शुक्रवार, 8 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के साथ तस्वीर साझा की। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा,'हम वो लोग नहीं हैं जो मुश्किल समय में एक-दूसरे का साथ छोड़ देते हैं।'

राजनीतिक हलकों में अखिलेश का यह बयान कांग्रेस के खिलाफ तंज के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही कांग्रेस ने तमिलनाडु में डीएमके से नाता

तोड़कर विजय की ळश्ङ सरकार को समर्थन देने का फैसला किया था।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अभिनेता विजय की पार्टी ळश्ङ ने अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। हालांकि बहुमत के लिए जरूरी 118 सीटों के आंकड़े से पार्टी अभी भी पीछे है।

कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों का समर्थन देकर विजय की दावेदारी को मजबूत किया है। लेकिन इसके साथ ही उसने डीएमके से दूरी बना ली, जिसने क्ठऊक्अ गठबंधन के भीतर नई बहस छेड़ दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस का यह कदम विपक्षी एकजुटता की राजनीति पर असर डाल सकता है, खासकर तब जब भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को साथ रखने की चुनौती पहले से मौजूद है।

दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव ने यह बयान ऐसे समय दिया है जब वे कोलकाता में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से मुलाकात कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में ळटउ की चुनावी हार के बाद यह मुलाकात विपक्षी राजनीति में नए समीकरणों की तरफ इशारा मानी जा रही है। +तस्वीर में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन की मौजूदगी ने संदेश को और स्पष्ट कर दिया। माना जा रहा है कि अखिलेश ने कांग्रेस को यह जताने की कोशिश की है कि क्षेत्रीय दलों के बीच भरोसे की राजनीति अभी भी कायम है।

वाम दलों की बैठकें, विजय के समर्थन पर फैसला आज

तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अब वाम दलों की भूमिका अहम हो गई है। चेन्नई में उढक(ट) की कार्यकारिणी बैठक जारी है, वहीं उढक की बैठक भी पार्टी कार्यालय में चल रही है। दोनों दलों के पास विधानसभा में 2-2 विधायक हैं। इसके अलावा विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) के भी 2 विधायक हैं।

दुनिया ने देखा 'मेक इन इंडिया' का दम, कैसे आर्मेनिया का सबसे बड़ा व भरोसेमंद हथियार सप्लायर बना भारत?

(जीएनएस)। दक्षिण काकेशस की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। कभी रूस का सबसे करीबी रहा आर्मेनिया अब अपनी सुरक्षा के लिए भारत और फ्रांस की ओर देख रहा है। यूक्रेन युद्ध में रूस के उलझने और अजरबैजान से मिली हार के बाद, आर्मेनिया का रूसी हथियारों से भरोसा टूट गया है।

अब भारत आर्मेनिया के लिए सबसे भरोसेमंद सैन्य साझीदार बनकर उभरा है। आर्मेनिया न केवल अपनी रक्षा जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है, बल्कि वह खुद को यूरोपीय नेटवर्क से जोड़कर रूस के प्रभाव से बाहर निकलना चाहता है।

एक समय था जब आर्मेनिया की सेना पूरी तरह रूसी हथियारों पर टिकी थी। लेकिन हालिया युद्धों में रूसी प्रणालियां अजरबैजान के आधुनिक ड्रोनों के सामने नाकाम साबित हुईं। इसके अलावा, रूस का ध्यान पूरी तरह यूक्रेन पर है, जिससे आर्मेनिया खुद को अकेला महसूस करने लगा। ऐसे में भारत ने एक 'सच्चे दोस्त' की तरह हाथ बढ़ाया।

भारत की हथियार प्रणालियां न केवल आधुनिक हैं, बल्कि किफायती और प्रभावी भी हैं। यही वजह है कि आर्मेनिया ने अपनी सुरक्षा की कमान अब भारतीय हथियारों को सौंप दी है।

आर्मेनिया ने भारत से युद्ध के मैदान में पासा पलटने वाले हथियार खरीदे हैं। इनमें पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ATAGS होवित्जर तोपें शामिल हैं। भारतीय रडार 'स्वाति' भी अब वहां की सीमाओं की निगरानी कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आर्मेनिया अपने सुखोई (Su-30) विमानों को भी भारतीय तकनीक से अपग्रेड कराना चाहता है। आज आर्मेनिया की तोपखाना और वायु रक्षा प्रणाली की रीढ़ पूरी तरह से 'मेड इन इंडिया' उत्पादों पर टिकी है।

भारत के लिए आर्मेनिया का साथ देना केवल व्यापार नहीं, बल्कि कूटनीति भी है। दरअसल, अजरबैजान को पाकिस्तान और तुर्की का खुला समर्थन हासिल है। पाकिस्तान अक्सर कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ अजरबैजान का साथ देता है।

'आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते'; नोएडा मजदूर प्रदर्शन के दौरान हिंसा मामले में गिरफ्तार छात्रा से बोला सुप्रीम कोर्ट

नोएडाः उत्तर प्रदेश के नोएडा में श्रमिक आंदोलन के दौरान पकड़ी छात्रा आकृति चौधरी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को नोएडा में औद्योगिक मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार एक छात्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले

की सुनवाई की। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने आकृति चौधरी की ओर से पेश वकील से इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा। बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाओं को भड़काने के मामले गिरफ्तारियां हुई हैं।

पेट्रोल-डीजल, गैस पर बड़ा संकट! होर्मुज में अभी भी फंसे हैं भारत के 41 टैंकर

(जीएनएस)। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। यह समुद्री रास्ता वैश्विक तेल और गैस सप्लाई के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है।

ताजा संकट की वजह से भारत आने वाले करीब 41 जहाज वहां फंस गए हैं, जिनमें कच्चा तेल, एलपीजी और खाद जैसे जरूरी सामान लदे हैं। अगर यह रास्ता जल्द नहीं खुला, तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सामानों की कीमतों पर बुरा असर पड़ सकता है।

होर्मुज स्ट्रेट ईरान और ओमान के बीच स्थित एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है। यह फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया का लगभग एक-तिहाई समुद्री तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे ताजा संघर्ष और गोलीबारी की वजह से इस रास्ते

पर जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई है। दोनों देशों की सेनाओं द्वारा की गई नाकेबंदी ने इस अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग को एक जंग के मैदान में बदल दिया है।

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर बहुत निर्भर है। वर्तमान में भारत आने वाले 40 से ज्यादा जहाज इस इलाके में फंसे हुए हैं। इनमें से 13 जहाजों पर भारत का झंडा लगा है। अधिकारियों ने प्राथमिकता के आधार पर 41 जहाजों की लिस्ट बनाई है जिन्हें जल्द निकालना जरूरी है। इनमें 18 टैंकरों में तेल और गैस है, जबकि 16 जहाजों में खेती के लिए जरूरी खाद है। इन जहाजों के रुकने से भारत में ईंधन की कमी हो सकती है।

तनाव की मुख्य वजह ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में हुए युद्धविराम का टूटना है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी सेना ने उसके तेल टैंकरों और तटीय इलाकों पर हमला करके समझौते का उल्लंघन किया है।

सम्पादकीय

राजनीति हिंसा का दाग

पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद की सबसे बड़ी हिंसक घटना में भाजपा नेता शुभेन्दु अधिकारी के सहयोगी चन्द्रनाथ रथ की नृशंस हत्या बुधवार की रात कर दी गई। एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी 42 वर्षीय रथ की हत्या से इतनी राजनीतिक बवंडर उठा है कि दूसरी राजनीतिक गतिविधियां अपने आप दब गई हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनाव हमेशा हिंसक रहे हैं। 1947 से 1971 तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, उस वक्त राज्य में हिंसक वातावरण नहीं था। किन्तु 1971 से 2011 तक कम्युनिस्ट सरकार के दौरान राज्य में चुनाव के पहले हिंसा इसलिए होती थी ताकि विपक्षी पार्टियों के समर्थक वोट न दे सकें। लेकिन ममता की सरकार ने 2011 से 2026 तक इस चुनावी हिंसा का विस्तार किया। इसके लिए टीएमसी वैडर ने चुनाव के बाद जिन लोगों ने उनकी पाटी को वोट नहीं दिया उन्हें सबक सिखाने के उद्देश्य से उनके साथ मार पीट करते रहे हैं। टीएमसी के कार्यकर्ता स्थानीय चुनावों में भाजपा, कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों की ओर से खड़े होने वाले प्रत्याशियों का नामांकन करने से रोक देते और यदि वे किसी तरह कोर्ट कचहरी की मदद से नामांकन करने में सफल भी हो गए तो उनके समर्थकों की खैर नहीं। विपक्षी कार्यकताओं और वोटरों की हत्याएं तो सामान्य बात है। चुनाव आयोग की सव्रियता और पश्चिम बंगाल पुलिस की अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण चुनाव के दौरान तो राजनीतिक हत्याएं नहीं हुई किन्तु चन्द्रनाथ रथ की हत्या के बाद लगता है कि राज्य में एक बार फिर हत्याओं का दौर शुरू हो जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस हत्या की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानि सीबीआई को सौंप कर सरकार ने सव्रियता दिखाई ताकि राज्य में भय का माहौल कायम न हो सके। केन्द्र ने अपनी सव्रियता का संदेश देने के लिए ही बृहस्पतिवार को विधानसभा भंग करके राज्यपाल को शासन अपने हाथ में लेने और सक्षम कार्रवाई के लिए प्रभावी संदेश दिया। बहरहाल पश्चिम बंगाल की रक्त संस्वृति का समापन तो निश्चित है किन्तु इसमें समय लगेगा क्योंकि जब तक बांगलादेशी घुसपैठियों का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता तब तक हिंसा की छिटपुट घटनाएं होती रहेंगी। फिलहाल अब राज्य में प्राथमिकताओं के हिसाब से नागरिक सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि किसी और की हत्या न हो सके। किन्तु इसके लिए राज्य में सबसे पहले स्थानीय पुलिस को राजनीतिक कार्यकर्ता से वापस पुलिस कमी तथा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को पुलिसिंग की एथिक्स सिखाना आवश्यक है। आने वाली सरकार के सामने यह बड़ी चुनौती होगी कि वह इतने बड़े पुलिस संगठन को वैसे सुधारे। लब्बोलुआब यह है कि पश्चिम बंगाल में लक्षित आपराधिक एवं हिंसक घटनाओं से छुटकारा दिलाने के लिए आने वाली नई सरकार को कई स्तर पर सव्रियता दिखानी होगी उसमें अब तक का सबसे प्रामाणिक माडल योगी सरकार का रहा है जिसे अपनाकर पश्चिम बंगाल को देश के शान्तिप्रिय राज्यों की सूची में शामिल किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद नई दिल्ली में यही सूत्र वाक्य बोला था कि 'बदला नहीं बदलाव की जरूरत' है।

योगी आदित्यनाथ के प्रयास को मिली बड़ी सफलता, अमेरिकी मल्टीनेशनल अडोबी ने नोएडा में खोला बड़ा दफ्तर

(जीएनएस)।

अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी अडोबी ने नोएडा में अपना नया ऑफिस खोलने की घोषणा की है। कंपनी ने नोएडा के 129 सेक्टर में 1.58 लाख वर्गफुट जगह लीज पर लिया है। इसमें 700 से भी अधिक कर्मचारी बैठ सकेंगे। यह कंपनी बीते 28 साल से भारत में काम कर रही है।

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी को ग्लोबल कंपनियों का हब बनाना चाहते हैं। उनके इस प्रयास को बड़ी सफलता मिली है। इनोवेटिव टूल्स और प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और पर्सनलाइज्ड ग्राहक अनुभव को बढ़ावा देने वाले ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर अडोबी (अड्डि) ने यूपी पर भरोसा जताया है। इस कंपनी ने शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर नोएडा में अपना नया ऑफिस खोलने की घोषणा की। यह कंपनी का भारत में 7वां और उत्तर प्रदेश में तीसरा ऑफिस है।

700 से अधिक लोग बैठेंगे

नोएडा के सेक्टर 129 स्थित मैक्स स्क्वायर में अडोबी का नया दफ्तर खोला गया है। कंपनी ने वहां 1.58 लाख वर्ग फुट जगह लीज पर लिया है। कंपनी का कहना है कि इस कैंपस में इंजीनियरिंग और ग्राहक-केंद्रित भूमिकाओं वाले 700 से अधिक कर्मचारी एक साथ बैठेंगे। इससे पता चलता है कि अब नोएडा पर मल्टीनेशनल कंपनियों का भरोसा तेजी से बढ़ रहा है।

इनोवेशन के भविष्य को मिलगा आकार

अडोबी इंडिया के कंट्री मैनेजर

और अडोबी के डॉक्यूमेंट क्लाउड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, अभिज्ञान मोदी का कहना है "जिस तरह से एआई और एजेंटिक टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही है, ऐसे में अडोबी सबसे आगे है - जो नई संभावनाओं की कल्पना कर रहा है और इनोवेशन के भविष्य को आकार दे रहा है। हर किसी को क्रिएट करने के लिए सशक्त बनाने का हमारा मिशन इस बदलाव के केंद्र में है, और अडोबी के एआई-संचालित भविष्य को आगे बढ़ाने में भारत की हमारी टीमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हमारे नए नोएडा ऑफिस का खुलना, भारत से इनोवेशन को बढ़ावा देने पर हमारे निरंतर फोकस में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

नई तकनीक से लैस

कंपनी का कहना है कि भारत में अडोबी का नया ऑफिस एक विश्व-स्तरीय कार्यस्थल के रूप में विकसित किया गया है। वहां एआई के युग में टीमों को सहयोग करने और क्रिएट करने के लिए नवीनतम तकनीक से लैस है। नएअडोबी ऑफिस में एक ऐसा माहौल बनाने पर कंपनी का फोकस है जहां लोग अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। अडोबी की सस्टेनेबिलिटी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप - नोएडा की यह नई इमारत आयजीबीसी प्लैटिनम-सर्टिफाइड है और इसमें पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी डिजाइन, एनर्जी-एफिसिएंट सिस्टम्स और टिकाऊ निर्माण प्रथाओं को शामिल किया गया है।

1997 में भारत आई थी कंपनी

अडोबी ने साल 1997 में भारत में प्रवेश किया था। तब एक इंजीनियरिंग फ्र&ऊसेंटर के रूप में भारत में अपना संचालन शुरू किया था। तब से यह कंपनी के प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इनोवेशन रणनीति के पीछे एक प्रेरक शक्ति बन गया है, जो इस क्षेत्र की कुछ बेहतरीन प्रतिभाओं को आकर्षित करता है। आज की तारीख में कंपनी के साथ 8,000 से अधिक लोग इसके यहां काम करते हैं। इसी के साथ, भारत अमेरिका के बाहर अडोबी का सबसे बड़ा वर्कफोर्स बन गया है। इस समय भारत इसके एक तिहाई से अधिक इनोवेशन में योगदान देता है।

ब्रह्मोस को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान ने बनाई फतह-3 मिसाइल? क्या है इसकी असलियत?

ब्रह्मोस को टक्कर देने के लिए ढÔkistÔ»»f ने बनाई FÔtÔh-3 मिसाइल? क्या है इसकी असलियत? क्यों हो रही इस पर चर्चा?

(जीएनएस)।

दुनिया में इस समय सैन्य ताकत को लेकर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा चल रही है। लगभग हर बड़ा देश अपनी सेना को पहले से ज्यादा आधुनिक और खतरनाक बनाने में लगा हुआ है। नए मिसाइल सिस्टम, स्टील्थ फाइटर जेट, अक आधारित हथियार, और एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी अब सिर्फ रक्षा का हिस्सा नहीं रह गई हैं, बल्कि ये देशों की जियो पॉलिटिकल ताकत तय करने लगी हैं। बस फर्क इतना के कि ज्यादातर देश खुद से टेक्नोलॉजी इजाद कर रहे हैं और पाकिस्तान चीन से लाकर अपने यहां अनबॉक्सिंग कर अपनी पीठ थपथपा लेता है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अब ब्रह्मोस को टक्कर देने के लिए एक बार फिर चीनी मिसाइल का अपने यहां परीक्षण किया है।

क्या है ये नई मिसाइल?

पाकिस्तान ने हाल ही में FATAH-3

सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को दुनिया के सामने रखा। इस मिसाइल को भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान इस मिसाइल के आर्मी में आ जाने से सीना चौड़ा कर घूम रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि यह चीन की लऊ-1 मिसाइल टेक्नोलॉजी कॉपी पेस्ट है। इसमें पाकिस्तान की मेहनत सिर्फ लॉन्च करने तक सीमित है, क्योंकि बाकी रिसर्च एंड डिवेलपमेंट का काम चीन में पहले ही पूरा हो चुका था। लेकिन पाकिस्तानी सरकार इसे मेड-इन पाकिस्तान बता रहा है।

क्या है खासियत?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी यानी अंतिम हमले के समय की रफ्तार मैक 2.5 से लेकर मैक 4 तक हो सकती है। इतनी तेज गति इसे खतरनाक स्ट्राइक वेपन बना देती है, क्योंकि दुश्मन के पास प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय बचता है।

जमीन और समुद्र के बेहद करीब उड़ान भरने की क्षमता

इस मिसाइल की एक और खासियत यह है कि यह जमीन की सतह से सटकर या समुद्र के ऊपर बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। सैन्य भाषा में इसे छङ्क्ष्द अ'३३४ीं र्ऋ३ ढ१ङ्क्ष'ी कहा जाता है। इसका फायदा यह होता है कि दुश्मन के रडार सिस्टम इसे जल्दी पकड़ नहीं पाते। कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से यह रडार की नजर से बचते हुए अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच सकती है।

एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ा खतरा

मिसाइल की लो-फ्लाइट क्षमता और हाई स्पीड पारंपरिक एयर डिफेंस नेटवर्क के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। एक्सपर्ट्स की मानें तो, इससे प्रतिद्वंदी के पास इंटरसेप्शन यानी मिसाइल को बीच में रोकने का समय बहुत कम रह जाता है। यही नहीं, यह मिसाइल रडार ट्रैकिंग, इंटरसेप्शन कैलकुलेशन और टारगेट लॉकिंग जैसी प्रक्रियाओं को भी उलझाने में सक्षम बताई जा रही है। आसान भाषा में कहें तो यह मिसाइल दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को भ्रमित करने के लिए डिजाइन की गई है।

पाकिस्तान से काफी आगे भारत

भारत भी डिफेंस सेक्टर में तेजी से विस्तार कर रहा है और कई देशों के साथ हथियार बाजार में सीधी टक्कर दे रहा है। भारत में बनने वाली कई मिसाइलें और फाइयर जेट अब दूसरे देशों द्वारा न सिर्फ खरीदे जा रहे हैं बल्कि पहली पसंद भी बन रहे हैं। हाल ही में वियतनाम और अजरबैजान जैसे कई देशों ने भारत से बड़ी डिफेंस डील की। इसके अलावा भारत बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन्स बनाने पर काम कर रहा है।

यहीं नहीं मलेशिया की फ्ट1.9 बिलियन की एयर डिफेंस प्रतियोगिता में भारत अपने स्वदेशी आकाश-1र और आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम पब्लिक किए जो चीन को सीधी टक्कर देते हैं। साथ ही भारत की आकाश मिसाइल डिफेंस को कम दूरी की एयर डिफेंस क्षमता के लिए काफी प्रभावी माना जाता है। यह दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। भारत अब अपने स्वदेशी हथियारों को ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट करने पर भी तेजी से फोकस कर रहा है।

शाहीन शाह अफरीदी ने रचा इतिहास, जो कोई पाकिस्तानी नहीं कर सका वो कर दिखाया, दिग्गजों की लिस्ट में हुई एंट्री!

(जीएनएस)।

पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने शुक्रवार को टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बांग्लादेश के खिलाफ ढाका में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन शाहीन ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में अपने 100 विकेट पूरे कर लिए। वे यह उपलब्धि हासिल करने वाले पाकिस्तान के पहले और दुनिया के चुनिंदा गेंदबाजों में शुमार हो गए हैं।

7वें ओवर की पहली गेंद पर रचा इतिहास

मैच शुरू होने से पहले शाहीन के नाम 28 मैचों में 99 विकेट दर्ज थे। ढाका टेस्ट के पहले ही सत्र में उन्होंने बांग्लादेशी ओपनर महमूदुल हसन जॉय को आउट कर अपना 100वां शिकार किया। शाहीन ने अपनी घातक इन-स्विंग पर जॉय को मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच कराया। शाहीन ने अब तक 29 हळळउ मैचों में 3 बार पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा भी किया है।

दिग्गजों के खास लिस्ट में शामिल हुए शाहीन

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन (224 विकेट) के नाम है। वहीं एशियाई गेंदबाजों की बात करें तो भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (195 विकेट) शीर्ष पर हैं, जिन्होंने दिसंबर 2024 में संन्यास ले लिया था। भारत के ही जसप्रीत बुमराह 185 विकेटों के साथ एशियाई गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। शाहीन अब 100 विकेट क्लब में शामिल होकर इन दिग्गजों की राह पर चल पड़े हैं।

कप्तानी का दबाव और प्रदर्शन

बाबर आजम के पहले टेस्ट से बाहर होने के बाद पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण की पूरी जिम्मेदारी शाहीन के कंधों पर है। 2023-2025 के चक्र में संघर्ष करने के बाद शाहीन ने इस नए सीजन की शुरूआत धमाकेदार अंदाज में की है। उनके इस प्रदर्शन ने साबित कर दिया है कि वे आधुनिक टेस्ट क्रिकेट के सबसे घातक बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों में से एक हैं।

पाकिस्तान के टॉप-3 गेंदबाज (WTC), शाहीन अफरीदीः 100 विकेट (29 मैच), नोमान अलीः 89 विकेट (20 मैच), साजिद खानः 63 विकेट (12 मैच)

अगर ट्रंप हारे मिड टर्म इलेक्शन तो जाएगी कुर्सी? कितनी संभावना और क्या कहता है अमेरिकी संविधान?

(जीएनएस)।

ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं वे एक के बाद एक वो फैसले ले रहे जिन्हें चुनाव लड़ने के दौरान उन्होंने अपने घोषणा पत्र में सिरे से खारिज कर दिया था। जैसे- ईरान या किसी भी दूसरे देश के साथ जंग शुरू करना या फिर अमेरिका में महंगाई कम करना। ट्रंप अपने सभी वादों से पलटते जा रहे हैं। वेनेजुएला और ईरान के साथ जंग लड़ चुके हैं और अमेरिका में महंगाई भी तेजी से बढ़ रही है। यही कारण है कि उन पर अमेरिका में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन (मध्यावधि चुनाव) में हारने का खतरा मंडरा रहा है। आइए जानते हैं कि क्या होता है मिड टर्म इलेक्शन, इसका अगले राष्ट्रपति चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इसमें ट्रंप के हारने के चांस क्या हैं और यदि हार गए तो आगे क्या होगा।

राषट्रपति का पावर चेक हैं मिड टर्म इलेक्शन

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जितने बड़े माने जाते हैं, उतने ही अहम होते हैं Midterm Elections. ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने तक सीमित

नहीं होते, बल्कि कई बार यह तय कर देते हैं कि अगले दो साल तक राष्ट्रपति कितनी ताकत से काम कर पाएंगे। आसान भाषा में कहें तो मिडटर्म चुनाव अमेरिका की राजनीति का पावर चेक होते हैं। 2026 में अमेरिका में फिर से Midterm Elections होने जा रहे हैं।

क्या होते हैं Midterm Elections.?

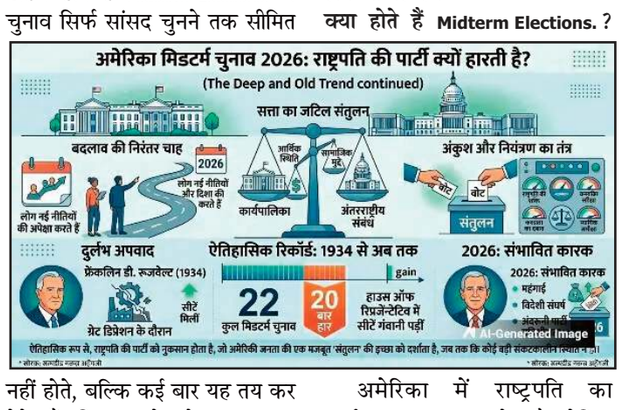

अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। लेकिन इस चार साल के बीच, यानी ठीक दो साल बाद, पूरे देश में फिर से चुनाव कराए जाते हैं। इन्हें ही Midterm Elections. कहा जाता है क्योंकि ये राष्ट्रपति के कार्यकाल के मिड पॉइंट यानी बीच में होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर राष्ट्रपति चुनाव 2024 में हुआ और राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का है, तो बीच के दो साल बाद यानी 2026 में Midterm Elections. होंगे।

2026 के Midterm Elections. के लिए प्राथमिक चुनाव (PrimÔry Electio»»fs) मार्च 2026 से शुरू होकर सितंबर 2026 के मध्य तक चलेंगे।

किन पदों के लिए होते हैं मिड टर्म इलेक्शन?

Midterm Elections. में कई तरह के चुनाव होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस अमेरिकी कांग्रेस पर रहता है। कांग्रेस अमेरिका की संसद जैसी संस्था है, जिसके दो हिस्से होते हैं-

- (हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव)
- U.S. (सीनेट)

2026 के चुनावों में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव की सभी 435 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके अलावा अमेरिकी सीनेट की 35 सीटों पर भी चुनाव होंगे। ये दोनों संस्थाएं अमेरिकी राजनीति में बेहद ताकतवर मानी जाती हैं क्योंकि यही कानून बनाती हैं और राष्ट्रपति के फैसलों को प्रभावित करती हैं।

राष्ट्रपति और कांग्रेस के बीच क्या रिश्ता होता है?

अमेरिका में राष्ट्रपति और कांग्रेस दोनों अलग-अलग तरीके से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति देश की Executive Branch यानी कार्यकारी शाखा को लीड करते हैं, जबकि कांग्रेस Legislative Branch यानी विधायी शाखा को कंट्रोल करती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कानून बनाने की असली ताकत कांग्रेस के पास होती है।

संकट की घड़ी में दुनिया की संजीवनी है रेडक्रॉस

विश्व रेडव्रॉस दिवस पर विशेष

रेडव्रॉस की स्थापना महान मानवता प्रेमी जीन हेनरी डयूनेंट द्वारा की गई थी, इसीलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष विश्वभर में 8 मई का दिन 'अंतर्राष्ट्रीय रेडव्रॉस दिवस' के रूप में मनाया जाता है और संस्था की गतिविधियों से आम आदमी को अवगत कराने के प्रयास किए जाते हैं। रेडव्रॉस की स्थापना वर्ष 1863 में हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय रेडव्रॉस सोसायटी दुनिया के सभी देशों में रेडव्रॉस आन्दोलन का प्रसार करने के साथ-साथ रेडव्रॉस के आधारभूत सिद्धांतों के संरक्षक के रूप में भी कार्य कर रही है। 8 मई 1828 को जन्मे डयूनेंट 1859 में हुई सालफिरोनो (इटली) की लड़ाई में घायल सैनिकों की दुर्दशा देख बहुत आहत हुए थे क्योंकि युद्धभूमि में पड़े इन घायल सैनिकों के उपचार के लिए कोई चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। युद्ध मैदान में घायल पड़े इन्हीं सैनिकों के दर्दनाक हालातों पर अपने कड़वे अनुभवों के आधार पर उन्होंने 'मेमोरी और सालफिरोनो' नामक एक पुस्तक भी लिखी और 1863 में रेडव्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति 'आईसीआरआई' का गठन किया। डयूनेंट के सतत प्रयासों की बदौलत ही 1864 में जेनेवा समझौते के तहत 'अंतर्राष्ट्रीय रेडव्रॉस मूवमेंट' की स्थापना हुई।

डयूनेंट ने इटली में युद्ध के दौरान रक्तपात का ऐसा भयानक मंजर देखा था, जब चिकित्सकीय सहायता के अभाव में युद्धक्षेत्र में अनेक घायल सैनिक हृदयविदारक कष्टों से तड़प रहे

थे। ऐसे घायलों की सहायता के लिए उन्होंने स्थायी समितियों के निर्माण की आवश्यकता को लेकर आवाज बुलंद की, जिसका असर भी दिखा। युद्ध में आहतों की स्थिति के सुधार के साधनों का अध्ययन करने के लिए उसके बाद एक आयोग का गठन किया गया। 1863 में जेनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में रेडव्रॉस के आधारभूत सिद्धांत निर्धारित किए गए तथा रेडव्रॉस आन्दोलन का विकास करते हुए आहत सैनिकों और युद्ध पीडितों की सहायता संगठित करने हेतु दुनियाभर के सभी देशों में राष्ट्रीय समितियां बनाने पर जोर दिया गया।

नेपोलियन तृतीय के हस्तक्षेप के चलते अंतर्राष्ट्रीय समिति 'स्विस पेडरल काउंसिल' को 8 अगस्त 1864 को जेनेवा में सम्मेलन बुलाने के लिए राजी करने में सफल हुई, जिसमें 26 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सम्मेलन के चलते जेनेवा अधिवेशन हुआ, जिसमें सुरक्षा के प्रतीक रेडव्रॉस वाले सपेद झंडे पर स्वीवृति की मोहर लगाई गई, जो आज समस्त विश्व में रेडव्रॉस का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है।

शुरूआती दौर में रेडव्रॉस की भूमिका युद्ध के दौरान बीमार और घायल सैनिकों, युद्ध करने वालों और युद्धबंदियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना तथा उन्हें उचित उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने तक ही सीमित थी किन्तु अब इस संस्था के दायित्वों का दायरा लगातार विस्तृत होता जा रहा है। मानवीय सेवा को सर्मपित रेडव्रॉस ने प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अनेक घायल सैनिकों तथा नागरिकों की सहायता कर अनुकरणीय उदाहरण पेश किया था। दुनिया के किसी भी भाग में जब भूकम्प, बाढ़, भू-स्खलन या अन्य किसी भी प्रकार की प्रावृतिक अथवा मानवीय आपदा सामने आती है तो सबसे पहले 'अंतर्राष्ट्रीय रेडव्रॉस सोसायटी' की टीमें वहां पहुंचकर राहत कार्यो में जुट जाती हैं। शांति और सौहार्द के प्रतीक के रूप में जानी जाने वाली इस संस्था ने अपने कर्मठ, सर्मपित और कत्र्तव्यनिष्ठ स्वयंसेवकों के माध्यम से न केवल भारत में बल्कि दुनियाभर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। फिलहाल 190 से भी अधिक देशों में 'रेडव्रॉस' संस्था सव्रिय है।

1800 करोड़ कमाने के बाद अब ओटीटी पर रिलीज हो रही 'धुरंधर 2'

(जीएनएस)।

बॉलीवुड के फेमस एक्टर रणवीर सिंह की हाई-वोल्टेज एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म 'धुरंधरः द रिवेंज' इन दिनों हर तरफ चर्चा में बनी हुई है। फिल्म ने सिनेमाघरों में जबरदस्त कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बना दिया है। अब जिन दर्शकों ने इसे बड़े पर्दे पर नहीं देखा, वो इसके ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

फिल्म 'धुरंधर 2' की लगातार सफलता के कारण इसकी डिजिटल रिलीज को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर हर दिन ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर 'धुरंधर 2' ऑनलाइन कब और किस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी।

-19 मार्च 2026 को रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर 2' ने रिलीज के कई हफ्तों बाद भी सिनेमाघरों में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म दुनियाभर में करीब 1800 करोड़ रुपये का कारोबार कर चुकी है और इसकी कमाई अभी भी थमती नजर नहीं आ रही है। फिल्म को

दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिलने की वजह से मेकर्स ने इसकी ओटटी रिलीज को थोड़ा आगे बढ़ाने का फैसला किया था। आमतौर पर बड़ी फिल्मों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने से पहले करीब 2 महीने का थिएट्रिकल विंडो रखा जाता है ताकि सिनेमाघरों की कमाई प्रभावित न हो।

-फिल्म 'धुरंधर 2' की ओटीटी रिलीज को लेकर अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक टाइटल कार्ड ने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'धुरंधर 2' आगामी 14 मई 2026 (गुरुवार) से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो सकती है।

-चर्चा ये भी है कि भारत में फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज किया जा सकता है जबकि इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए इसे नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध कराया जा सकता है। हालांकि मेकर्स की ओर से अब तक किसी भी प्लेटफॉर्म की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

-फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर सामने आई एक और दिलचस्प जानकारी ने फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ओटीटी पर रिलीज होने वाला वर्जन थिएटर कट से थोड़ा लंबा हो सकता है।

-बताया जा रहा है कि डिजिटल वर्जन का रनटाइम करीब 3 घंटे 53 मिनट होगा, जो सिनेमाघरों में रिलीज हुए वर्जन से कुछ मिनट ज्यादा है। माना जा रहा है कि इसमें कुछ अनदेखे और एक्सटेंडेड सीन्स भी शामिल किए जा सकते हैं, जिन्हें थिएटर रिलीज में जगह नहीं मिली थी।

-रणवीर सिंह की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्लोबल मार्केट में भी बड़ी सफलता हासिल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 'धुरंधर 2' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन तेजी से 1800 करोड़ रुपये के आंकड़े की ओर बढ़ रहा है।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com»garvigujarat2007@yahoo.com»Website : www.garvigujarat.co.in

आईपीआरडी मंत्री श्रवण कुमार ने संभाला पदभार, भ्रामक सूचनाओं पर सख्ती के दिए निर्देश

(जीएनएस)।

मंत्री श्रावण कुमार के नेतृत्व वाला बिहार का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सोशल मीडिया के माध्यम से जनसंपर्क बढ़ाने, अफवाहों के खिलाफ जानकारी की पुष्टि करने और समय पर, सटीक सार्वजनिक संचार सुनिश्चित करने तथा राज्य की सकारात्मक छवि को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण सूचना नेटवर्क को मजबूत करने की योजना बना रहा है।

बिहार सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (आईपीआरडी) के मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को विभाग का पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर विभागीय सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह, निदेशक अनिल कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका वे पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सरकार के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक है, जिसकी जिम्मेदारी आम लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अधिक से अधिक उपयोग कर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत और भ्रामक खबरों की तथ्यात्मक जांच कर विभाग के आधिकारिक हैंडल से तत्काल खंडन किया जाए, ताकि लोगों के बीच किसी प्रकार का भ्रम न फैले। मंत्री ने कहा कि विभाग का मुख्य फोकस सूचनाओं के सही, सटीक और समयबद्ध प्रसारण पर रहेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाई जाएगी।

श्रवण कुमार ने बिहार की सकारात्मक छवि को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत बनाने की जरूरत पर बल दिया।

बुजुर्ग महिलाओं का सहारा बनी योगी सरकार, 29 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिल रही वृद्धावस्था पेंशन

(जीएनएस)।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही वृद्धावस्था पेंशन योजना लाखों बुजुर्ग महिलाओं के लिए बड़ा सहारा बनकर सामने आई है. राज्य सरकार इस समय 29,23,364 बुजुर्ग महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दे रही है. आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद महिलाओं के लिए यह योजना राहत का बड़ा माध्यम बन रही है.

योगी सरकार की ओर से योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है. डीबीटी के जरिए हर तीन महीने में 3,000 रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाते हैं. नियमित पेंशन

मिलने से बुजुर्ग महिलाओं की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हो रही हैं और उनमें आत्मनिर्भरता व आत्मसम्मान की भावना भी मजबूत हुई है.

समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के अनुसार, वृद्धावस्था पेंशन योजना पूरी पारदर्शिता के साथ चलाई जा रही है. पेंशन की राशि सीधे बैंक खातों में भेजे जाने से बिचौलियों की भूमिका खत्म हुई है और लाभ समय पर पात्र महिलाओं तक पहुंच रहा है. इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक मदद मिली है. प्रदेश में जौनपुर जिला इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी जिला बनकर सामने आया है. यहां 1,00,820 बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन मिल रही है. इसके बाद आजमगढ़ में 86,166 और बलिया में 79,160 महिलाओं को योजना का लाभ मिल रहा है.

सरकार का कहना है कि लगातार पात्र महिलाओं की पहचान कर उन्हें योजना से जोड़ा जा रहा है, ताकि कोई भी जरूरतमंद महिला लाभ से वंचित न रहे. नियमित आर्थिक सहायता मिलने से बुजुर्ग महिलाओं को दवा, राशन और दूसरी जरूरी चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है. खासकर ग्रामीण इलाकों में यह योजना महिलाओं के लिए सम्मान के साथ जीवन जीने का आधार बन रही है.

अब सीवर के पानी से होगा निर्माण और पार्कों की सिंचाई!

दिल्ली सरकार बना रही प्लान

(जीएनएस)।

दिल्ली में तेजी से गिरते भूजल स्तर और बढ़ते पानी संकट के बीच अब राजधानी में पानी बचाने को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। दिल्ली सरकार ऐसी नई नीति तैयार कर रही है, जिसके तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी से निकलने वाले ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल निर्माण कार्यों, पार्कों की सिंचाई और दूसरे गैर-पीने वाले कामों में किया जाएगा। सरकार का मानना है कि अगर पीने योग्य साफ पानी की जगह ट्रीटेड वेस्टवॉटर का इस्तेमाल बढ़ाया जाए, तो दिल्ली में भूजल पर दबाव काफी हद तक कम हो सकता है।

दिल्ली के लोक निर्माण और जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में सरकारी निर्माण परियोजनाओं में ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल अनिवार्य किया जा सकता है। यही वजह है कि दिल्ली जल बोर्ड नई पॉलिसी पर तेजी से काम कर रहा है।

दिल्ली लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रही है। आबादी लगातार बढ़ रही है, लेकिन जमीन के नीचे मौजूद पानी तेजी से खत्म हो रहा

है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की 2024 की रिपोर्ट ने इस संकट को और गंभीर तरीके से सामने रखा है।

रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के 34 तहसीलों में सेः

14 'ओवर एक्सप्लॉइटेड' यानी जरूरत से ज्यादा भूजल निकालने वाले क्षेत्र हैं।

13 तहसीलें 'क्रिटिकल' कैटेगरी में हैं।

सिर्फ 5 इलाके ही सुरक्षित माने गए हैं।

यानी राजधानी जितना पानी जमीन से निकाल रही है, उतना वापस रिचार्ज नहीं हो पा रहा। इसी वजह से सरकार अब वैकल्पिक जल स्रोतों की तरफ बढ़ रही है।

दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली विकास प्राधिकरण पहले से ही कुछ जगहों पर ट्रीटेड पानी का इस्तेमाल बागवानी और हरित क्षेत्रों में कर रहे हैं। अभी करीब 89 मिलियन गैलन प्रतिदिन यानी 89 एमजीडी ट्रीटेड पानी अलग-अलग सरकारी एजेंसियों को सप्लाई किया जा रहा है।

इन एजेंसियों में शामिल हैंः

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद

नगर निगम दिल्ली

लेकिन अब सरकार इसे और बड़े स्तर पर लागू करना चाहती है। नई नीति का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जहां पीने योग्य पानी की जरूरत नहीं है, वहां ट्रीटेड सीवेज वॉटर का इस्तेमाल किया जाए।

दिल्ली सरकार सबसे पहले सरकारी निर्माण परियोजनाओं में इस पानी के उपयोग पर फोकस कर रही है। इसके बाद निजी कंपनियों को भी सस्ती दरों पर यह पानी उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा सकती है।

हालांकि इसके लिए तकनीकी मानकों का पालन जरूरी होगा। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाले पानी के लिए कुछ गाइडलाइन तय की हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर खराब गुणवत्ता वाला पानी इस्तेमाल किया गया तो इससे लोहे और कंक्रीट को नुकसान पहुंच सकता है और निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। सरकार अब राजधानी के पार्कों, ग्रीन बेल्ट और रोडसाइड गार्डन में भी बड़े स्तर पर ट्रीटेड पानी पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पाइपलाइन नेटवर्क तैयार किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ इलाकों में छोटे और स्थानीय स्तर के डीसेंट्रलाइज्ड एसटीपी लगाने की भी योजना है।

सुवेंदु अधिकारी के एक इशारे पर गूंज उठा 'नरेंद्र मोदी जिंदाबाद', वीडियो वायरल

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल की राजनीति में सुवेंदु अधिकारी एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं। हाल ही में, पश्चिम बंगाल भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अपने संबोधन के दौरान उन्होंने एक उत्साहपूर्ण माहौल बना दिया।

सुवेंदु ने वहां मौजूद सभी समर्थकों और विधायकों से खड़े होने का आग्रह किया और पूरे जोश के साथ "नरेंद्र मोदी जिंदाबाद" के नारे लगवाए। उनके इस कदम ने पार्टी कार्यकताओं में नया जोश भर दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया है।

सुवेंदु अधिकारी को सर्वसम्मति से पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना गया। कोलकाता में हुई भाजपा की अहम बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी। इस चुनाव के साथ ही पार्टी ने यह साफ कर दिया कि वह ममता बनर्जी के खिलाफ सुवेंदु के आक्रामक रुख पर भरोसा करती है। सुवेंदु ने इस जिम्मेदारी को बड़ी विनम्रता से स्वीकार किया और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया, जिससे बंगाल भाजपा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है।

वहीं विधायक दल का नेता चुने जाने के तुरंत बाद सुवेंदु ने अपने भाषण में कार्यकताओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने न केवल अपनी जीत पर चर्चा की, बल्कि सभी को एकजुट होकर काम करने की प्रेरणा दी। भाषण के अंत में उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को अपनी सीटों से खड़े होने के लिए कहा। उन्होंने हाथ उठाकर बेहद उत्साह के साथ "नरेंद्र मोदी जिंदाबाद" के नारे लगाए। इस दृश्य ने यह साबित किया कि सुवेंदु बंगाल में भाजपा की विचारधारा को और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे।

सुवेंदु अधिकारी का यह व्यवहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनके अटूट विश्वास और सम्मान को प्रकट करता है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि बंगाल में भाजपा की बढ़त के पीछे मोदी का चेहरा और उनकी लोकप्रियता सबसे बड़ा कारण है। नारों के माध्यम से उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि बंगाल भाजपा पूरी तरह से दिल्ली के नेतृत्व के साथ खड़ी है। यह उनके और प्रधानमंत्री के बीच के मजबूत राजनीतिक तालमेल को भी दशार्ता है।

बंगाल की राजनीति पर असर

सुवेंदु के इस आक्रामक और जोशीले अंदाज से राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष के नेता के रूप में उनकी सक्रियता बताती है कि आने वाले समय में विधानसभा के अंदर और बाहर सत्ताधारी दल को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। उनके समर्थकों का मानना है कि सुवेंदु का यह नेतृत्व भाजपा को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करेगा। इस घटना ने बंगाल के राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है।

रूपा गांगुली : बंगाल डिप्टी सीएम बनने की होगी अहम वजह!

(जीएनएस)।

पश्चिम बंगाल के 2026 विधानसभा चुनाव ने न सिर्फ सत्ता का समीकरण बदला, बल्कि भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग की मास्टरस्ट्रेटजी को भी उजागर कर दिया। भाजपा ने 293 सीटों पर 206 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया। सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जबकि दो उप-मुख्यमंत्री पदों के लिए रेस तेज है। इनमें रूपा गांगुली का नाम सबसे आगे है।

सोनारपुर दक्षिण से उनकी बड़ी जीत के पीछे सिर्फ 10 साल की मेहनत या टीएमसी विरोध नहीं, बल्कि उनकी जातीय पहचान भी अहम भूमिका निभा रही है। तो सवाल ये है - रूपा गांगुली की जाति क्या है? और यह डिप्टी सीएम पद की दौड़ में क्यों निर्णायक साबित हो सकती है? आइए समझते हैं...

रूपा गांगुली का उपनाम गांगुली बंगाली हिंदू समाज में मुख्य रूप से कुलीन ब्राह्मण समुदाय से जुड़ा है।

यह बंगाली ब्राह्मणों की राढ़ी शाखा का हिस्सा है, जिसकी जड़ें 11वीं शताब्दी में कन्नौज (कान्यकुब्ज) ब्राह्मणों के बंगाल प्रवास से जुड़ी हैं। पारंपरिक रूप से इसे गंगोपाध्याय कहा जाता है, जो गंगा किनारे के गांव से आने वाले पुजारी/आचार्य का अर्थ रखता है।

फैमिली बैकग्राउंडः पिता समरेंद्र लाल गांगुली और मां जुथिका गांगुली। कलकत्ता विश्वविद्यालय से जुड़े जोगोमाया देवी कॉलेज से बीएससी (1986)। परिवार बंगाली ब्राह्मण परंपरा का हिस्सा रहा है।

धार्मिक-सांस्कृतिक पहचानः बंगाल में कुलीन ब्राह्मण ऐतिहासिक रूप से विद्वान, पुजारी और सामाजिक रूप से प्रभावशाली रहे हैं। हालांकि आबादी में ब्राह्मण सिर्फ 7-8% के आसपास हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों, बौद्धिक वर्ग और नौकरशाही में उनका प्रभाव काफी है।

रूपा गांगुली को देशभर में बीआर चोपड़ा के महाभारत में द्रौपदी के रोल से पहचान मिली। बंगाली सिनेमा, टीवी और संगीत में सक्रिय रहने के बाद 2015 में उन्होंने भाजपा जॉइन की। पार्टी ने उन्हें बंगाली महिला चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट किया।

2015-16: पश्चिम बंगाल भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनीं। महिला सुरक्षा, राजनीतिक हिंसा के खिलाफ अभियान चलाए। 2016 विधानसभाः हावड़ा नॉर्थ से लड़ीं, लेकिन हार गईं। 2016: राज्यसभा सांसद बनीं (नवजोत सिंह सिद्धू की सीट पर नामांकन)।

गोरखपुर के धुरियापार में इसी माह होगा अंबुजा सीमेंट प्लांट का शिलान्यास, सीएम योगी कार्यक्रम में होंगे शामिल

(जीएनएस)।

गोरखपुर। पूर्वांचल के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के अंतर्गत विकसित हो रहे धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र में अदाणी समूह की अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास इसी माह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों होने की संभावना है। प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है और 20 से 30 मई के बीच कार्यक्रम आयोजित होने की उम्मीद जताई जा रही है।

अदाणी की ओर से प्रस्तावित योजना के अनुसार करीब 1400 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाली यह फैक्ट्री धुरियापार चीनी मिल परिसर के पास लगभग 46 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी। फैक्ट्री शुरू होने के बाद करीब एक हजार लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है, जबकि परिवहन, निर्माण, होटल, व्यापार और अन्य सहायक गतिविधियों में हजारों अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होंगे।

कंपनी ने ऐसी जमीन का चयन किया है, जो प्रस्तावित सहजनवा-दोहरीघाट रेल लाइन के बेहद करीब है। इससे कच्चे माल की ढुलाई और तैयार उत्पाद के परिवहन में आसानी होगी। बेहतर रेल और सड़क कनेक्टिविटी के कारण धुरियापार क्षेत्र निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है।

धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप में अदाणी समूह के अलावा कई अन्य बड़े औद्योगिक घराने भी निवेश की तैयारी कर रहे हैं। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहां कैंपा कोला का बाटलिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है, जबकि श्रेयस ग्रुप डिस्टिलरी और एथेनाल प्लांट लगाने की प्रक्रिया में है। वहीं, जेके सीमेंट ने भी यहां अपनी यूनिट स्थापित करने के लिए जमीन की मांग की है।

औद्योगिक परियोजनाओं की बढ़ती संख्या के चलते धुरियापार को अब 'पूर्वांचल का नोएडा' कहा जाने लगा है। लिंक एक्सप्रेसवे, रेल नेटवर्क और औद्योगिक कारिडोर की बेहतर कनेक्टिविटी आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र को पूर्वी उत्तर प्रदेश का बड़ा औद्योगिक केंद्र बना सकती है।

बदल जाएगी धुरियापार और आसपास के क्षेत्र की तस्वीर

अदाणी समूह की सीमेंट फैक्ट्री और अन्य प्रस्तावित उद्योगों के आने से धुरियापार क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक स्वरूप तेजी से बदलने की उम्मीद है। चेंबर आफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आरएन सिंह और लघु उद्योग भारती के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक कारीवाल का कहना है कि धुरियापार में बड़े उद्योगों की स्थापना से स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए महानगरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा।

परिवहन, होटल, गोदाम, छोटे व्यापार और निर्माण कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। भूमि की कीमतों में वृद्धि के साथ बाजार और आवासीय गतिविधियां भी तेज होंगी। सड़क, बिजली, पानी और संचार जैसी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। औद्योगिक निवेश के चलते धुरियापार आने वाले समय में पूर्वांचल के प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में उभर सकता है।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है। जल्द ही इसकी स्वीकृति मिलने की संभावना है। 20 मई के बाद किसी दिन शिलान्यास का कार्यक्रम संभव है । उन्होंने कहा कि धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र में बड़े निवेश आने से गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। -अनुज मलिक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा

मुख्यमंत्रियों का दिल भी कभी-कभार हो जाता है बच्चा जी, योगी आदित्यनाथ व पुष्कर सिंह धामी ने की कसरत

(जीएनएस)।

लखनऊ। लंबे समय तक राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य में उलझे रहने वाले मुख्यमंत्रियों का दिल भी कभी-कभार बच्चों जैसा हो जाता है।

ऐसा शुक्रवार को पौड़ी गढ़वाल में के यमकेश्वर क्षेत्र में देखने को मिला, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ओपन जिम के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। दोनों मुख्यमंत्री ने बच्चों जैसी जो हरकतें कीं, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर के दो दिवसीय दौरे पर हैं। शुक्रवार को उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी थे और दोनों को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह क्षेत्र यमकेश्वर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ एक ओपन जिम का शुभारंभ किया। इसके बाद दोनों ने कई उपकरणों पर अभ्यास भी किया। इस दौरान दोनों ने हंसते और खिलखिलाते हुए कसरत की वीडियो वायरल हो रही है। दोनों को बच्चों की तरह हंसते-खिलखिलाते देख लोग भी कहने लगे कि दिल तो बच्चा है जी।

सीएम योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर में एक मंदिर के उद्घाटन और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उनके दो दिवसीय यमकेश्वर दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय बिथ्याणी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी एक मंदिर के उद्घाटन और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर शनिवार को महायज्ञ होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिथ्याणी में महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय पहुंचे में अपने पूज्य गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात, एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला जब सीएम योगी ने कॉलेज परिसर के समीप बने ओपन एयर जिम का शुभारंभ किया। महज औपचारिकता न निभाते हुए, मुख्यमंत्री योगी और मुख्यमंत्री धामी ने खुद जिम के उपकरणों पर एक्सरसाइज (कसरत) की।

भगवाधारी मुख्यमंत्री ने ओपन जिम में बहाया पसीना

भगवाधारी मुख्यमंत्री को जिम में पसीना बहाते देख वहां मौजूद युवा और स्थानीय लोग जोश से भर गए। यह संदेश साफ था कि 'विकसित प्रदेश के लिए स्वस्थ नागरिक' पहली प्राथमिकता है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने क्षेत्र के प्रसिद्ध यमकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। पंचूर गांव की गलियों में जैसे ही योगी आदित्यनाथ का काफिला पहुंचा, स्थानीय महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने अपने 'गांव के लाल' का फूलों की वर्षा के साथ स्वागत किया। पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल है और लोग अपने प्रिय नेता की एक झलक पाने को बेताब दिखे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है। पंचूर और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि धार्मिक व व्यक्तिगत कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा, "योगी जी का अपने पैतृक गांव पहुंचना पूरे उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है। उनका अपनी जड़ों से यह लगाव हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है।

पंचूर गांव में आयोजित होने वाला यह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में संतों और श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है।

योगी आदित्यनाथ का यह दौरा साबित करता है कि वे भले ही देश के सबसे बड़े राज्य की कमान संभाल रहे हों, लेकिन उनकी आत्मा आज भी पहाड़ की इन्हीं कंदराओं और अपने गांव की मिट्टी में बसती है।

आईपीएल 2026 के बीच मचा बड़ा बवाल, स्टार क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड ने की शर्मनाक हरकत? बीसीसीआई ने लिया कड़ा एक्शन!

(जीएनएस)।

इंडियन प्रीमियर लीग के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने फैंस के मन में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक आईपीएल खिलाड़ी की गर्लफ्रेंड पर टीम की गोपनीय जानकारियां बाहर शेयर करने के गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना एक बार नहीं बल्कि दो बार हुई है, जिसके बाद बीसीसीआई (BCCI) अब सख्त कदम उठाने की तैयारी में है।

बीसीसीआई के पास पहुंची शिकायत

मामले का खुलासा तब हुआ जब एक फ्रेंचाइजी को अपनी टीम की आंतरिक रणनीतियों के लीक होने का आभास हुआ। जांच में एक खिलाड़ी की महिला मित्र की भूमिका संदिग्ध पाई गई। क्रिकब्लॉगर की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंचाइजी मालिकों ने तुरंत बीसीसीआई से संपर्क कर इस तरह की हरकतों की शिकायत की और खेल की अखंडता बनाए रखने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।

क्या आईपीएल से खत्म होगा गर्लफ्रेंड कल्चर?

इस घटना के बाद बीसीसीआई अब आईपीएल के दौरान खिलाड़ियों के साथ रहने वाली उनकी महिला मित्रों और पार्टनर को लेकर नए प्रोटोकॉल पर चर्चा कर रहा है। बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि भविष्य में गर्लफ्रेंड कल्चर पर पूर्ण प्रतिबंध या बेहद कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। टीम की रणनीतिक बैठकों के दौरान परिजनों या पार्टनर की मौजूदगी पूरी तरह प्रतिबंधित हो सकती है।

किस खिलाड़ी की है गर्लफ्रेंड नहीं हुआ है खुलासा

इसके अलावा संवेदनशील जानकारी के लीक होने से बचाने के लिए खिलाड़ियों और उनके करीबियों के लिए नए डिजिटल प्रोटोकॉल लागू किए जा सकते हैं। यदि कोई भी खिलाड़ी या सहयोगी स्टाफ नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उन पर भारी जुमार्ना या निलंबन की कार्रवाई हो सकती है।

इस सीजन में हार्दिक पंड्या, यशस्वी जायसवाल, अर्शदीप सिंह और ईशान किशन जैसे कई बड़े खिलाड़ी अपनी पार्टनर के साथ नजर आए हैं। हालांकि, रिपोर्ट में किसी विशेष खिलाड़ी या उनकी गर्लफ्रेंड के नाम का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इस विवाद ने सभी फ्रैंचाइजी को सतर्क कर दिया है।

उत्तराखंडः पैतृक गांव पंचूर में सीएम योगी ने की 'हरि विष्णु पंचदेव मंदिर' की प्राण प्रतिष्ठा, जागरण में भी हुए शामिल

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर (उत्तराखंड) के दो दिवसीय दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने न केवल नवनिर्मित मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की, बल्कि अपने पैतृक घर में रात बिताते हुए पहाड़ी संस्कृति और परंपराओं का आनंद भी लिया.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उत्तराखंड के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर में नवनिर्मित 'हरि विष्णु पंचदेव मंदिर' में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की. सीएम योगी 7 मई की दोपहर हेलीकॉप्टर से अपने गांव पहुंचे थे, जहां ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया. उन्होंने गुरुवार की रात अपने पैतृक आवास पर बिताई और स्थानीय 'जागर' (जागरण) अनुष्ठान में भाग लिया. शुक्रवार सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान विष्णु, गणेश, शंकर, मां दुर्गा और हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित की गईं. इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने जिम का उद्घाटन भी किया.

योगी आदित्यनाथ जब अपने गांव पहुंचे, तो वह एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उस मिट्टी के बेटे के रूप में नजर आए. गुरुवार की रात बेहद भावुक रही, जब उन्होंने अपने पुराने घर में समय बिताया. पहाड़ों की ठंडी हवाओं के बीच रातभर देवताओं के आह्वान की परंपरा 'जागर' का आयोजन हुआ. सीएम योगी ने न केवल इस धार्मिक उत्सव में हिस्सा लिया, बल्कि ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी बातें भी सुनीं. बच्चों के साथ उनकी आत्मीय बातचीत ने सबका दिल जीत लिया.

8 मई की तारीख पंचूर गांव के इतिहास में दर्ज हो गई. नवनिर्मित 'हरि विष्णु पंचदेव मंदिर' की दिव्यता देखते ही बनती है. इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां भगवान विष्णु के साथ प्रथम पूज्य गणेश, महादेव, आदि शक्ति मां दुर्गा और संकटमोचन हनुमान जी की मूर्तियां एक साथ स्थापित की गई हैं. शुक्रवार सुबह मंदिर की घंटियों और वैदिक मंत्रों की गूंज के बीच योगी जी ने पूर्ण श्रद्धा के साथ अनुष्ठान संपन्न कराया.

प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें आसपास के दर्जनों गांवों के लोग शामिल हुए. इस दौरे का एक और दिलचस्प नजारा पौड़ी के महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय में दिखा. यहां ओपन जिम की शुरूआत के मौके पर मुख्यमंत्री फिटनेस के अंदाज में नजर आए. उन्होंने जिम के उपकरणों का जायजा लिया और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया. ग्रामीणों के लिए अपने 'योगी जी' को इतने करीब से देखना किसी उत्सव से कम नहीं था.

जड़ों की ओर एक आध्यात्मिक यात्रा

योगी आदित्यनाथ का यह दो दिवसीय दौरा महज एक राजनीतिक दौरा नहीं, बल्कि अपनी जड़ों की ओर वापसी की एक आध्यात्मिक यात्रा बताई जा रही है. इस कार्यकाल में यह उनका अपने गांव का लगातार तीसरा दौरा है. मंदिर, मूर्तियां और अपनों का साथ- पंचूर से विदा लेते समय सीएम योगी की आंखों में एक अलग ही संतोष और सुकून दिखाई दे रहा था.

भाजपा जनकल्याण मंच की गूगल मीटिंग सम्पन्न – संगठन को मिला सशक्त दिशा-निर्देश

भाजपा जनकल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दर्शन आर शाह जी के सानिध्य एवं मयंक जी के नेतृत्व में संगठन के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकताओं की महत्वपूर्ण गूगल मीटिंग सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तीनों प्रदेशों में भाजपा की ऐतिहासिक विजय पर सभी कार्यकताओं को हार्दिक बधाई दी और इसे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व, निर्णायक नीतियों और जनकल्याणकारी सोच पर जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाजपा का मूल मंत्र ह्लसबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वासह्व केवल नारा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का अटूट संकल्प है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को चेताते हुए कहा कि अब समय केवल बैठकों का नहीं, बल्कि मैदान में उतरकर जनता के बीच काम करने का है। हर कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाए और विपक्ष के झूठ, भ्रम एवं दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब सेवा, सत्य और विकास के माध्यम से दे।

उन्होंने भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए साधु-संतों के सम्मान एवं गौमाता की रक्षा को राष्ट्र का गौरव बताया। गौमाता को ह्लराष्ट्रीय माताह्व घोषित कराने के लिए देशव्यापी जनआंदोलन को तेज करने का आह्वान किया गया। इसके तहत सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे तहसीलदार, डीएम, एसडीएम एवं संबंधित मंत्रियों को ज्ञापन सौंपकर इस मांग को मजबूती से रखें। बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया कि जन सुनवाई एवं जनता दरबार के माध्यम से आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे संगठन की जमीनी पकड़ और अधिक सुदृढ़ हो सके।

इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पंडित संतोष मिश्रा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री रामलाल वैष्णव जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री रवि शर्मा जी, पंकज जी, मनोज जी, लक्ष्मी जी सहित महिला मोर्चा, किसान मोर्चा एवं युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

अनुशासन पर सख्त संदेशः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट और कड़े शब्दों में निर्देश दिया कि भविष्य में किसी भी बैठक में सभी पदाधिकारियों—प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, उपाध्यक्ष, महामंत्री, संगठन महामंत्री एवं सभी जिला अध्यक्षों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा। यदि कोई पदाधिकारी अत्यावश्यक कारणवश उपस्थित नहीं हो सकता, तो उसे पूर्व में लिखित सूचना प्रदेश या राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना अनिवार्य होगा।

अंत में संगठन विस्तार पर विशेष बल देते हुए कहा गया कि भाजपा जनकल्याण मंच को देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए सभी कार्यकताओं को तत्काल प्रभाव से सक्रिय होना होगा और अपने आचरण से संगठन की गरिमा को सर्वोपरि रखना होगा। 'मजबूत संगठन, सशक्त राष्ट्र — यही हमारा संकल्प है।'

बालेन शाह के अड़ियल रुख से दिल्ली तक हलचल! भारतीय विदेश सचिव ने रद्द किया नेपाल का दौरा

(जीएनएस)।

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री का प्रस्तावित नेपाल दौरा रद्द होना दक्षिण एशियाई राजनीति में एक बड़ी हलचल माना जा रहा है। काठमांडू पोस्ट के अनुसार, यह यात्रा 11 मई को होनी थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है।

इस दौरे का मुख्य उद्देश्य नेपाल की नई बालेन शाह सरकार के साथ संबंधों की नींव रखना था। हालांकि, भारत ने इसके पीछे व्यस्तताओं का हवाला दिया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह द्वारा मुलाकात से इनकार करना इस फैसले की सबसे बड़ी वजह बनी है।

नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र (बालेन) शाह ने भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मिलने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। रिपोर्टों के अनुसार, बालेन शाह ने एक नीति बनाई है कि वे केवल राष्ट्राध्यक्षों या विदेश मंत्रियों से ही सीधे बात करेंगे, किसी अधिकारी या दूत से नहीं। उनके इसी अड़ियल रुख के कारण भारतीय पक्ष को लगा कि बिना शीर्ष स्तर की मुलाकात के इस दौरे का कूटनीतिक महत्व कम हो जाएगा, जिसके बाद यात्रा टाल दी गई।

यात्रा रद्द होने के पीछे दूसरा बड़ा कारण लिपुलेख ट्राईजंक्शन को लेकर उपजा ताजा विवाद है। भारत और चीन ने मानसरोवर यात्रा शुरू करने को लेकर जो सहमति जताई थी, उस पर बालेन शाह सरकार ने आपत्ति दर्ज कराई है। नेपाल इस क्षेत्र को अपना मानता है और बिना उसकी सहमति के किए गए किसी भी फैसले को अपनी संप्रभुता के खिलाफ देखता है। इस तनावपूर्ण माहौल ने बातचीत की गुंजाइश को फिलहाल कम कर दिया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि बालेन शाह फिलहाल भारत, चीन और अमेरिका के बीच चल रही 'जियो-पॉलिटिक्स' (भू-राजनीति) से खुद को दूर रखना चाहते हैं। उनका पूरा ध्यान नेपाल के स्थानीय मुद्दों और विकास पर है। उन्होंने न केवल भारत, बल्कि अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों और राजदूतों से भी मिलने से मना कर दिया है। बालेन शाह का यह संदेश साफ है कि वे बाहरी दखल के बजाय घरेलू प्राथमिकताओं को ज्यादा महत्व दे रहे हैं।

विक्रम मिस्री की इस यात्रा का मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बालेन शाह को दिल्ली आने का न्यौता देना था। दौरे के रद्द होने से दोनों देशों के बीच भविष्य के रिश्तों की दिशा फिलहाल धुंधली पड़ गई है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के अधिकारी चाहते थे कि यह मुलाकात हो ताकि दशकों पुरानी दोस्ती और मदद का सिलसिला बना रहे, लेकिन बालेन शाह के कड़े रुख ने कूटनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है।

जेआईडब्लूओ और ज्ञान गंगोत्री काव्य मंच के कार्यक्रमों में सांस्कृतिक गौरव एवं देशभक्ति का सुंदर संगम

मुंबई, 8 मई। संस्कृति, साहित्य, प्रतिभा और राष्ट्र भावना से ओत-प्रोत दो भव्य कार्यक्रमों का सफल आयोजन सुप्रसिद्ध साहित्यकार, वरिष्ठ समाजसेवी एवं लोढ़ा साहेब की प्रेरणा एवं नेतृत्व में प्रारम्भ हुई संस्था खक्हड साउथ मुंबई चैप्टर आज महिलाओं को संस्कृति, सेवा और सशक्तिकरण से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है। लोढ़ा पार्क में आयोजित खक्हड साउथ मुंबई चैप्टर टैलेंट कॉम्पिटिशन में विभिन्न प्रतिभागियों ने जैन समाज एवं भारतीय संस्कृति पर आधारित नृत्य, संगीत, अभिनय और अन्य प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में महिलाओं और समूहों ने पूरे आत्मविश्वास और उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सुश्री शालिनी पीरामल, डॉ. करेन टेरी रजा तथा सुप्रसिद्ध अभिनेत्री एवं समाजसेविका सुश्री दिलजोत विशेष अतिथियों के रूप में उपस्थित रहीं और उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के पश्चात सभी खक्हड सदस्यों ने गरबा नृत्य का आनंद लिया, जिससे वातावरण उल्लास और उमंग से भर गया। प्रतियोगिता में विजेता बने सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की गई। इसी क्रम में लोढ़ा कोस्टेरिया में आयोजित ज्ञान गंगोत्री काव्य मंच का काव्य मिलन कार्यक्रम भी अत्यंत सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इसका विषय था ह्लआपकी पसंदीदा जगहह्व, जिसमें विभिन्न कवियों और साहित्य प्रेमियों ने अपनी सुंदर रचनाओं के माध्यम से भावपूर्ण अभिव्यक्तियाँ प्रस्तुत कीं। इसी अवसर पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय का भी उत्सव मनाया गया। इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी गईं। उपस्थित सभी लोगों ने देश की प्रगति, विकास और मजबूत नेतृत्व के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया। दोनों आयोजन श्रीमती मंजू लोढ़ा के सशक्त नेतृत्व, सांस्कृतिक सोच और सामाजिक समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण बने। सुश्री इंदिरा खींवसरा ने कार्यक्रमों का सफल संचालन किया। श्रीमती मंजू लोढ़ा ने सफल आयोजन के लिए दोनों संस्थाओं की सभी सदस्याओं के प्रति आभार प्रकट किया।

जैन इंटरनेशनल वुमैन ऑर्गेनाइजेशन (JIWO) और ज्ञान गंगोत्री काव्य मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के विभिन्न दृश्य।

श्रीमती लोढ़ा जहाँ जैन इंटरनेशनल वूमेन ऑर्गनाइजेशन (JIWO) के साउथ मुंबई चैप्टर की अध्यक्षा हैं, वहीं वे ज्ञान गंगोत्री काव्य मंच की संस्थापक-अध्यक्षा भी हैं। दोनों आयोजनों में उत्साह, रचनात्मकता, सांस्कृतिक गौरव और देशभक्ति का सुंदर संगम देखने मिला। जैन समाज की परम पूज्य विदुषी आर्या श्री मयणाश्रीजी महाराज फाउंडेशन की अध्यक्षा श्रीमती मंजू लोढ़ा के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में सम्पन्न हुआ।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहा था चीन, पहली बार खुद कबूला सच

(जीएनएस)।

भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले साल हुए सैन्य संघर्ष (ऑपरेशन सिंदूर) को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पहली बार चीन ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि उसने युद्ध के दौरान पाकिस्तान को ऑन-ग्राउंड तकनीकी मदद दी थी।

चीनी सरकारी मीडिया के जरिए सामने आए इस कबूलनामे ने भारत के उन दावों पर मुहर लगा दी है, जिनमें चीन की सक्रिय भूमिका की बात कही गई थी। यह खुलासा न केवल दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ाएगा, बल्कि दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन और चीनी हथियारों की साख पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन (AVIC) के इंजीनियर झांग हेंग ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह संघर्ष के दौरान पाकिस्तान में मौजूद थे। उन्होंने पुष्टि की कि उनकी टीम वहां फाइटर जेट्स और अन्य तकनीकी उपकरणों को चौबीसों घंटे चालू रखने के लिए काम कर रही थी। मई की भीषण गर्मी और एयर-रेड सायरन के बीच चीनी इंजीनियर पाकिस्तानी वायुसेना को तकनीकी बैकअप दे रहे थे। यह साबित करता है कि पाकिस्तान की सैन्य शक्ति के पीछे चीन का सीधा हाथ था।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अपने रक्षा तंत्र को भारतीय वायुसेना के खिलाफ परखा, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान के पास मौजूद एकीकृत वायु रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां भारतीय हमलों को रोकने में नाकाम रहीं। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई एयरफील्ड, रडार सिस्टम और हैंगर को भारी नुकसान पहुंचाया। इस ऑपरेशन ने यह साफ कर दिया कि युद्ध की वास्तविक परिस्थितियों में पाकिस्तानी सुरक्षा घेरा काफी कमजोर साबित हुआ। चीन ने अपने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को पश्चिमी देशों के सिस्टम से बेहतर बताया था, लेकिन भारत के खिलाफ यह पूरी तरह फ्लॉप रहा। दावा किया गया था कि यह लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली भारतीय विमानों को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसने से रोकेगी, मगर हकीकत में यह रणनीतिक ठिकानों की रक्षा नहीं कर पाई। चीनी हथियारों पर पाकिस्तान का जो भरोसा था, वह इस संघर्ष के बाद बुरी तरह डगमगा गया है और चीनी तकनीक की साख गिर गई है।

झांग हेंग के खुलासे से यह स्पष्ट है कि यह केवल भारत और पाकिस्तान का आपसी टकराव नहीं था। चीन ने न केवल हथियार बेचे, बल्कि युद्ध के मैदान में अपने तकनीकी विशेषज्ञ तैनात करके सक्रिय हिस्सेदारी निभाई। झांग ने बताया कि कैसे उनकी टीम 50 डिग्री तापमान में भी उपकरणों को पूरी क्षमता पर रखने की कोशिश कर रही थी।

सुवेंदु अधिकारी : नंदीग्राम के महानायक से बंगाल के मुख्यमंत्री तक!

पश्चिम बंगाल में सालों तक वामपंथ और फिर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के दबदबे वाले इस राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी (इखढ) की सरकार बनने जा रही है। इस ऐतिहासिक बदलाव के महानायक कोई और नहीं, बल्कि सुवेंदु अधिकारी हैं। सुवेंदु अधिकारी बंगाल के सीएम बनने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस में कभी ममता बनर्जी के सबसे खास सिपहसालार रहे सुवेंदु अधिकारी आखिर कैसे भाजपा के सबसे बड़े चेहरे बन गए? उनके राजनीतिक सफर में कितने उतार-चढ़ाव आए?

सुवेंदु अधिकारी को साल 2020 तक ममता बनर्जी का राइट हैंड माना जाता था। लेकिन पार्टी में ममता के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव ने उनको धीरे-धीरे हाशिए पर पहुंचा दिया। इसके बाद सुवेंदु अधिकारी 021 के चुनाव के ठीक पहले भाजपा में आ गए। ऐसे में आइए जानते हैं सुवेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफरनामा, उनके परिवार का इतिहास।

सुवेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर 1970 को पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के कारकुली में हुआ था। सुवेंदु को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता शिशिर अधिकारी बंगाल की राजनीति के बेहद सम्मानित और कद्दावर नेता रहे हैं। शिशिर अधिकारी मनमोहन सिंह की दूसरी यूपीए (UPA) सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और साल 2019 में कांथी लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। सुवेंदु की माता का नाम गायत्री अधिकारी है।

सुवेंदु अधिकारी शिक्षाः सुवेंदु ने साल 2011 में रवींद्र भारती विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ आर्ट्स (M.A.) की डिग्री हासिल की।

सुवेंदु अधिकारी ने नहीं की शादीः सुवेंदु अधिकारी को व्यक्तिगत जीवन में बेहद सादगी पसंद है। सुवेंदु

अधिकारी ने शादी नहीं की है और वे अविवाहित रहे हैं।

छात्र राजनीति से आगाजः सुवेंदु अधिकारी के राजनीतिक जीवन की नींव छात्र जीवन में ही पड़ गई थी, जब वे कांथी के पीके कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे थे। साल 1989 में वे कांग्रेस के छात्र संगठन 'छात्र परिषद' के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे।

भले ही आज सुवेंदु अधिकारी भाजपा के बड़े नेता हैं, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन की शुरूआत कांग्रेस पार्टी से हुई थी।

साल 1995: सुवेंदु पहली बार कांथी नगर पालिका में कांग्रेस के टिकट पर पार्षद चुने गए थे।

साल 1998: जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) बनाई, तो सुवेंदु भी उनके साथ चले गए।

साल 2006: वे कांथी दक्षिण सीट से विधानसभा का चुनाव जीते और उसी साल कांथी नगर पालिका के अध्यक्ष भी बने।

नगरपालिका अध्यक्षः विधायक बनने के बाद उसी साल (2006) उन्हें कांथी नगरपालिका का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

हालांकि उनका करियर 90 के दशक में शुरू हुआ, लेकिन 2007 के नंदीग्राम भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन ने उन्हें एक बड़े नेता के रूप में स्थापित किया। साल 2007 में पश्चिम बंगाल की तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार ने नंदीग्राम में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (रऐ) स्थापित करने के लिए लगभग 10,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने का फैसला किया। इस फैसले के खिलाफ स्थानीय किसानों में भारी रोष था।

यहीं से सुवेंदु अधिकारी की असली ताकत दुनिया के सामने आई। उन्होंने 'भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी' का गठन किया और नंदीग्राम भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन की कमान अपने हाथों में ले ली। इस आंदोलन ने न केवल बंगाल की बल्कि देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया और इसी आंदोलन की बदौलत ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता के केंद्र में स्थापित हुईं। हालांकि तत्कालीन वामपंथी सरकार की पुलिस (CID) ने सुवेंदु पर माओवादियों को हथियार सप्लाई करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए थे। नंदीग्राम में उनके ही प्रयासों का नतीजा था कि इलाके के सबसे प्रभावशाली सीपीएम नेता लक्ष्मण सेठ को हार का सामना करना पड़ा।

नंदीग्राम आंदोलन की सफलता के बाद ममता बनर्जी ने सुवेंदु को जंगल महल (पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुड़ा) का प्रभारी बनाया, जहां उन्होंने टीएमसी के संगठन को बेहद मजबूत किया।

संसद से लेकर राज्य के कैबिनेट मंत्री तक का सफर

सुवेंदु अधिकारी का कद लगातार बढ़ रहा था। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने तामलुक सीट से चुनाव लड़ा और माकपा (उढक-ट) के कद्दावर नेता लक्ष्मण सेठ को लगभग 1 लाख 73 हजार वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। इसके बाद 2014 में भी वे इसी सीट से सांसद चुने गए।

साल 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने उन्हें फिर से नंदीग्राम से मैदान में उतारा, जहां उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और ममता बनर्जी की कैबिनेट में परिवहन मंत्री (2016-2020) के रूप में शपथ ली। इसके बाद साल 2018 में उन्हें सिंचाई और जल संसाधन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। धीरे-धीरे अपनी सांगठनिक कुशलता के कारण वे ममता सरकार में 'नंबर दो' की हैसियत तक पहुंच गए थे और ळटउ में सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र बन गए। साल 2020 आते-आते तृणमूल कांग्रेस के भीतर सुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच वर्चस्व की जंग तेज हो गई।

जिन फ्लैटों का प्रधानमंत्री मोदी ने किया था लोकार्पण, दो साल में ही हो गए जर्जर, बदहाली पर कोर्ट ने मांगा जवाब

(जीएनएस)।

इंदौर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए लाइट हाउस प्रोजेक्ट के फ्लैटों की बदहाली को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत हुई है। याचिका में कहा है कि वर्ष 2023 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के फ्लैट दो साल में ही ऐसे हो गए हैं कि इनमें रहना मुश्किल हो गया है। फ्लैटों में लीकेज, दीवारों में दरारें और करंट फैलने जैसी समस्याएं हैं।

लोहे के स्ट्रक्चर पर बने इन फ्लैटों में जंग लगने लगी है। लगातार पानी रिसने के कारण घरों और बाथरूम में करंट फैलने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे लोगों की सुरक्षा खतरे

में पड़ गई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्क सुनने के बाद नगर निगम सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता नरेंद्र गोस्वामी की ओर से एडवोकेट अनुराग जैन ने यह याचिका प्रस्तुत की है। गौरतलब है कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया था। इसके तहत 1024 फ्लैट बने थे। याचिका में फ्लैटों की दीवारों में दरार, कमरों और बाथरूम में पानी रिसाव तथा करंट फैलने जैसी समस्याओं का उल्लेख किया गया है। रहवासियों का कहना है कि वे कई बार नगर निगम कार्यालयों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ।

याचिका में मांग की है कि रहवासियों को सुरक्षित और मजबूत सीमेंट-कंक्रीट निर्माण वाले फ्लैट उपलब्ध कराए जाएं। कोर्ट ने तर्क सुनने के बाद निगमायुक्त से कहा है कि वे रहवासियों की शिकायतों के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।